SHIKSHA SAMVAD
International Journal of Multidisciplinary Research
ISSN: 2584-0983 (Online)
© Shiksha Samvad|Volume-03| Issue-03| March- 2026
Available online at: https://shikshasamvad.com/

झाँसी जिले में सरकारी योजनाओं द्वारा स्नातक विद्यार्थियों के व्यक्तित्व एवं कौशल विकास का अध्ययन

रहीस अली[1], डॉ. धर्मेंद्र सिंह[2]
शोधार्थी, शिक्षा विभाग, विक्रांत विश्वविद्यालय, ग्वालियर[1]
एसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, विक्रांत विश्वविद्यालय, ग्वालियर[2]

सार:

प्रस्तुत शोध-पत्र झाँसी जिले के स्नातक विद्यार्थियों के व्यक्तित्व एवं कौशल विकास पर भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के प्रभाव का अध्ययन करता है। भारत में बुंदेलखंड क्षेत्र, विशेषकर झाँसी जिला, शैक्षिक एवं रोजगार दृष्टि से चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है, जहाँ युवा बेरोजगारी की दर 2020-21 में 24.6 प्रतिशत तक रही। इस अध्ययन का उद्देश्य प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस), उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन (यूपीएसडीएम) तथा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) के प्रभाव का मूल्यांकन करना है। शोध में वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध अभिकल्प अपनाया गया तथा 320 स्नातक विद्यार्थियों से प्रश्नावली के माध्यम से प्राथमिक सामग्री संग्रहित की गई। परिकल्पना यह थी कि सरकारी योजनाओं में सहभागिता करने वाले विद्यार्थियों में व्यक्तित्व लक्षणों एवं कौशलों का स्तर सहभाग न करने वालों की तुलना में उच्चतर होगा। परिणामों से ज्ञात हुआ कि सहभागी विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता, संप्रेषण कौशल, सामाजिक उत्तरदायित्व एवं रोजगार-योग्यता में सांख्यिकीय रूप से सार्थक वृद्धि हुई ($p < 0.05$)। निष्कर्ष यह है कि सरकारी योजनाएँ झाँसी के युवाओं के समग्र विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, परंतु जागरूकता एवं क्रियान्वयन में सुधार की आवश्यकता है।

मुख्य शब्द: सरकारी योजनाएँ, व्यक्तित्व विकास, कौशल विकास, स्नातक विद्यार्थी, झाँसी जिला

1. प्रस्तावना

भारत विश्व का सबसे युवा राष्ट्र है जहाँ की कुल जनसंख्या का लगभग 27 प्रतिशत भाग 15 से 29 आयु वर्ग में आता है, और आगामी वर्षों में प्रत्येक वर्ष लगभग 70 से 80 लाख नए युवा श्रम बल में सम्मिलित होंगे (अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, 2024)। यह जनसांख्यिकीय लाभांश तभी सार्थक सिद्ध होगा जब इन युवाओं को समुचित शिक्षा, व्यक्तित्व विकास एवं रोजगार-परक कौशल प्राप्त होगा। भारत जैसे विकासशील देश में स्नातक स्तर का विद्यार्थी न केवल अकादमिक ज्ञान चाहता है, अपितु ऐसे व्यावहारिक कौशल भी चाहता है जो उसे श्रम बाजार में प्रतिस्पर्धी बना सकें। चिंता का विषय यह है कि भारत में 50 प्रतिशत से अधिक स्नातक विद्यार्थी स्नातक होने के पश्चात भी रोजगार-योग्य नहीं माने जाते (व्हीबॉक्स इंडिया स्किल रिपोर्ट, 2021)। 2021 में भारत की युवा बेरोजगारी दर 20.82 प्रतिशत रही जो वैश्विक औसत से कहीं अधिक है (विश्व बैंक, 2021)।

उत्तर प्रदेश का झाँसी जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रमुख शैक्षिक केंद्र है, जहाँ बुंदेलखंड विश्वविद्यालय एवं उससे संबद्ध 175 से अधिक महाविद्यालयों में लाखों विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र की भौगोलिक एवं सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियाँ, अपर्याप्त औद्योगिक विकास, सूखा-प्रवण कृषि व्यवस्था तथा प्रवासन की प्रवृत्ति के कारण यहाँ के युवाओं को विशेष चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन परिस्थितियों में सरकारी योजनाओं की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण हो जाती है। केंद्र एवं राज्य सरकारों ने स्नातक विद्यार्थियों के व्यक्तित्व एवं कौशल विकास हेतु अनेक योजनाएँ संचालित की हैं, यथा 1969 में आरंभ की गई राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस), 2015 में प्रारंभ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन तथा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। इन योजनाओं का मूल उद्देश्य युवाओं को न केवल तकनीकी कौशल से सुसज्जित करना है, अपितु उनमें नेतृत्व, सामाजिक उत्तरदायित्व, संप्रेषण क्षमता, समस्या-समाधान दृष्टि एवं उद्यमिता जैसे गुण विकसित करना भी है (कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, 2021)। तथापि इन योजनाओं की वास्तविक प्रभावशीलता का जिला स्तरीय मूल्यांकन अभी अपर्याप्त है। झाँसी जैसे क्षेत्रीय संदर्भ में यह अध्ययन इसलिए महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह नीति-निर्माताओं, शैक्षिक संस्थानों एवं विद्यार्थियों को व्यावहारिक अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है। प्रस्तुत शोध इसी आवश्यकता की पूर्ति का प्रयास है (शर्मा एवं सक्सेना, 2020)।

2. साहित्य समीक्षा

विद्यार्थी जीवन में व्यक्तित्व एवं कौशल विकास पर सरकारी योजनाओं के प्रभाव का विश्लेषण करते हुए अनेक शोधकर्ताओं ने महत्त्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रस्तुत की है। भारती एवं आनंद (2021) ने कानपुर के आचार्य नरेंद्र देव नगर निगम महिला महाविद्यालय में 70 विद्यार्थियों पर किए गए अपने अध्ययन में पाया कि एनएसएस सहभागी एवं गैर-सहभागी विद्यार्थियों के व्यक्तित्व लक्षणों में सार्थक अंतर है तथा एनएसएस सहभागी छात्राओं में आत्मविश्वास, सामाजिक चेतना एवं समूह कार्य की भावना उच्चतर पाई गई। पाण्डेय (2015) ने नासिक के अशोका शिक्षा महाविद्यालय के 25 एनएसएस स्वयंसेवकों पर सात-दिवसीय विशेष शिविर का प्रभाव अध्ययन किया एवं पूर्व-परीक्षण (माध्य = 5.54) तथा पश्चात्-परीक्षण (माध्य = 9.77) के मध्य सांख्यिकीय रूप से सार्थक अंतर पाया, जिससे सिद्ध हुआ कि एनएसएस के विशेष शिविर सामाजिक एवं व्यक्तिगत मूल्यों के विकास में प्रभावी हैं। राव एवं वुप्पुलूरी (2015) ने अनुराग विश्वविद्यालय के स्नातक विद्यार्थियों पर अध्ययन कर बताया कि एनएसएस सहभागिता से सामाजिक चेतना, समुदाय में नेतृत्व का आत्मविश्वास तथा स्वैच्छिकता में सार्थक वृद्धि होती है। सेठी एवं अन्य (2019) ने भारतीय दंत-चिकित्सा विद्यार्थियों पर शोध करते हुए पाया कि एनएसएस से उनके संप्रेषण कौशल, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता एवं सामाजिक उत्तरदायित्व में $p \leq 0.05$ स्तर पर सार्थक सुधार हुआ। मेहरोत्रा (2014) ने लखनऊ विश्वविद्यालय में बीस वर्ष के एनएसएस अनुभव के आधार पर निष्कर्ष दिया कि सामुदायिक कार्य से शिक्षकों एवं विद्यार्थियों दोनों में बारह प्रमुख व्यक्तित्व लक्षण विकसित होते हैं।

कौशल विकास के संदर्भ में राव (2018) ने पीएमकेवीवाई 2.0 का विश्लेषण कर पाया कि उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षित अभ्यर्थियों में से केवल 6.95 प्रतिशत को रोजगार मिल सका, जबकि मध्य प्रदेश में यह दर 9.21 प्रतिशत तथा तमिलनाडु में 31.68 प्रतिशत रही। चौधरी एवं वर्मा (2020) ने अपने व्यवस्थित साहित्य समीक्षा में पाया कि एनएसडीसी, एनएसडीए तथा पीएमकेवीवाई जैसी संस्थाओं ने तकनीकी परिवर्तनों के युग में कौशल विकास हेतु महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है, परंतु सिद्धांत एवं व्यवहार के मध्य अंतराल, माँग एवं पूर्ति का असंतुलन तथा प्रशिक्षित प्रशिक्षकों की कमी प्रमुख बाधाएँ हैं। यथीश कुमार एवं रम्या (2017) ने अपने अध्ययन में पाया कि बहुसंख्य उत्तरदाता स्किल इंडिया अभियान से अवगत हैं, यद्यपि स्व-रोजगार अपनाने में अनेक समस्याएँ हैं। घोष एवं कुमार (2021) ने भारत के बढ़ते रोजगार संकट पर लिखते हुए तर्क दिया कि उच्च आर्थिक वृद्धि के बावजूद उच्च-शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी की दर अधिक है। अहमद (2016) ने राष्ट्रीय कौशल विकास नीति 2015 का विवेचन कर बताया कि 2022 तक 40.29 करोड़ कुशल श्रमिक तैयार करने का लक्ष्य था। ये सभी अध्ययन यह संकेत देते हैं कि सरकारी योजनाएँ व्यक्तित्व एवं

कौशल विकास में सहायक हैं, परंतु जिला-स्तरीय एवं विशेषकर बुंदेलखंड क्षेत्र पर शोध सीमित है, जो प्रस्तुत अध्ययन की प्रासंगिकता को रेखांकित करता है।

3. उद्देश्य

1. झाँसी जिले के स्नातक विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास पर एनएसएस तथा अन्य सरकारी योजनाओं के प्रभाव का अध्ययन करना।
2. पीएमकेवीवाई, यूपीएसडीएम एवं डीडीयू-जीकेवाई के अंतर्गत स्नातक विद्यार्थियों के कौशल विकास एवं रोजगार-योग्यता का मूल्यांकन करना।

4. शोध-प्रविधि

प्रस्तुत अध्ययन में वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध अभिकल्प का प्रयोग किया गया है क्योंकि इसका उद्देश्य घटना का यथार्थ चित्रण तथा कारण-संबंधी विश्लेषण करना है। अध्ययन का जनसंख्या-समुच्चय झाँसी जिले के बुंदेलखंड विश्वविद्यालय एवं उससे संबद्ध महाविद्यालयों में अध्ययनरत स्नातक विद्यार्थी हैं। न्यादर्श के चयन में स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन प्रविधि का उपयोग किया गया, जिसमें पुरुष-स्त्री, शहरी-ग्रामीण तथा सरकारी योजना सहभागी एवं गैर-सहभागी वर्गों का संतुलन सुनिश्चित किया गया। कुल न्यादर्श आकार 320 विद्यार्थी निर्धारित किया गया, जिनमें से 160 विद्यार्थी सरकारी योजनाओं (एनएसएस, पीएमकेवीवाई, यूपीएसडीएम) में सहभागी थे तथा 160 गैर-सहभागी थे। प्राथमिक सामग्री संग्रह हेतु संरचित प्रश्नावली उपकरण के रूप में प्रयुक्त की गई, जिसमें पाँच-बिंदु लिकर्ट मापनी पर आधारित 45 कथन सम्मिलित थे। प्रश्नावली के तीन प्रमुख खंड थे: व्यक्तिगत विवरण, व्यक्तित्व लक्षण मापनी (आत्मविश्वास, नेतृत्व, सामाजिक उत्तरदायित्व, भावनात्मक स्थिरता) तथा कौशल मापनी (संप्रेषण, तकनीकी, समस्या-समाधान, टीम-कार्य, उद्यमिता)। प्रश्नावली की विश्वसनीयता क्रोनबाख अल्फा द्वारा परीक्षित की गई जो 0.84 आई, जो उच्च विश्वसनीयता दर्शाता है। द्वितीयक सामग्री कौशल विकास मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, पीएमकेवीवाई पोर्टल, खुले सरकारी आँकड़ा मंच, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की रिपोर्ट तथा शोध पत्रिकाओं से एकत्रित की गई। सामग्री का विश्लेषण एसपीएसएस सॉफ्टवेयर 25.0 के माध्यम से किया गया, जिसमें वर्णनात्मक सांख्यिकी (माध्य, मानक विचलन, प्रतिशत) तथा अनुमानित सांख्यिकी (टी-परीक्षण, चि-वर्ग परीक्षण, सहसंबंध गुणांक) का प्रयोग किया गया। सार्थकता स्तर 0.05 निर्धारित किया गया। नैतिक मानकों का पालन करते हुए सभी प्रतिभागियों से सूचित सहमति प्राप्त की गई एवं उनकी पहचान गोपनीय रखी गई। शोध की समय अवधि जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक थी।

5. परिणाम एवं विश्लेषण

तालिका 1: भारत में पीएमकेवीवाई के अंतर्गत राज्यवार प्रशिक्षित अभ्यर्थी (2015-2021)

क्रम	राज्य	प्रशिक्षित अभ्यर्थी (लाख)	नियोजित अभ्यर्थी (लाख)	नियोजन दर (%)
1	उत्तर प्रदेश	15.90	3.39	21.3
2	मध्य प्रदेश	9.00	2.20	24.4
3	राजस्थान	8.90	1.85	20.8
4	तमिलनाडु	6.50	2.06	31.7
5	तेलंगाना	4.20	1.47	35.1

स्रोत: इंडिया स्पेंड (2022); पीएमकेवीवाई पोर्टल आँकड़े

तालिका 1 भारत में पीएमकेवीवाई के अंतर्गत 2015 से 2021 तक राज्यवार प्रशिक्षण एवं नियोजन की स्थिति दर्शाती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 15.90 लाख अभ्यर्थी प्रशिक्षित हुए परंतु नियोजन दर मात्र 21.3 प्रतिशत रही। तेलंगाना ने सर्वाधिक 35.1

प्रतिशत नियोजन दर अर्जित की, जबकि उत्तर प्रदेश में यह दर अपेक्षाकृत कम है। यह आँकड़े दर्शाते हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षण की मात्रा अधिक होने के बावजूद रोजगार-नियोजन में सुधार की आवश्यकता है।

तालिका 2: झाँसी जिले के न्यादर्श विद्यार्थियों का जनांकिकीय विवरण (n = 320)

श्रेणी	उप-श्रेणी	संख्या	प्रतिशत (%)
लिंग	पुरुष	178	55.6
	स्त्री	142	44.4
आयु	18-20 वर्ष	156	48.8
	21-23 वर्ष	164	51.2
क्षेत्र	शहरी	148	46.3
	ग्रामीण	172	53.7
योजना सहभागिता	सहभागी	160	50.0
	गैर-सहभागी	160	50.0

स्रोत: क्षेत्र-अध्ययन सर्वेक्षण आँकड़े (2021)

तालिका 2 में न्यादर्श का जनांकिकीय वितरण प्रस्तुत है। कुल 320 उत्तरदाताओं में 55.6 प्रतिशत पुरुष एवं 44.4 प्रतिशत स्त्रियाँ हैं। 53.7 प्रतिशत विद्यार्थी ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, जो बुंदेलखंड के ग्रामीण-प्रधान स्वरूप को दर्शाता है। न्यादर्श में सहभागी एवं गैर-सहभागी का बराबर अनुपात (50:50) है, जो तुलनात्मक विश्लेषण हेतु उपयुक्त है। 21-23 वर्ष आयु वर्ग की अधिकता स्नातक के द्वितीय एवं तृतीय वर्ष को इंगित करती है।

तालिका 3: सरकारी योजनाओं की जागरूकता (n = 320)

योजना का नाम	जागरूक विद्यार्थी (%)	सहभागी विद्यार्थी (%)
राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस)	78.4	28.1
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	64.7	14.4
उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन	52.3	9.7
दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना	38.6	5.3
स्किल इंडिया डिजिटल हब	41.2	7.8

स्रोत: क्षेत्र-अध्ययन सर्वेक्षण आँकड़े (2021)

तालिका 3 दर्शाती है कि एनएसएस के प्रति विद्यार्थियों में सर्वाधिक 78.4 प्रतिशत जागरूकता है, जबकि सहभागिता मात्र 28.1 प्रतिशत तक सीमित है। पीएमकेवीवाई की जागरूकता 64.7 प्रतिशत है परंतु वास्तविक सहभागिता केवल 14.4 प्रतिशत रही। डीडीयू-जीकेवाई एवं स्किल इंडिया डिजिटल हब के प्रति जागरूकता न्यूनतम है। इन आँकड़ों से जागरूकता एवं सहभागिता के बीच सार्थक अंतराल स्पष्ट होता है, जो प्रचार-प्रसार में सुधार की आवश्यकता संकेतित करता है।

तालिका 4: सहभागी एवं गैर-सहभागी विद्यार्थियों के व्यक्तित्व लक्षणों का तुलनात्मक विश्लेषण

व्यक्तित्व लक्षण	सहभागी माध्य	गैर-सहभागी माध्य	टी-मान	p-मान
आत्मविश्वास	4.12	3.34	8.76	<0.001
नेतृत्व क्षमता	4.08	3.21	9.42	<0.001
सामाजिक उत्तरदायित्व	4.21	3.18	11.05	<0.001
भावनात्मक स्थिरता	3.98	3.45	5.34	<0.001
टीम-कार्य भावना	4.15	3.38	8.21	<0.001

स्रोत: क्षेत्र-अध्ययन सर्वेक्षण आँकड़े; एसपीएसएस विश्लेषण (2021)

तालिका 4 स्पष्ट करती है कि सरकारी योजनाओं में सहभागी विद्यार्थियों के सभी व्यक्तित्व लक्षणों के माध्य गैर-सहभागियों से उच्चतर हैं तथा यह अंतर $p < 0.001$ स्तर पर अति-सार्थक है। सामाजिक उत्तरदायित्व में सर्वाधिक अंतर (टी = 11.05) पाया गया, जो योजनाओं की सामुदायिक सेवा प्रकृति का प्रतिफल है। नेतृत्व क्षमता एवं आत्मविश्वास में भी सहभागियों ने उल्लेखनीय श्रेष्ठता प्रदर्शित की, जो एनएसएस के विशेष शिविरों एवं सामूहिक गतिविधियों का सकारात्मक परिणाम दर्शाता है।

तालिका 5: कौशल स्तरों का तुलनात्मक विश्लेषण

कौशल	सहभागी माध्य	गैर-सहभागी माध्य	प्रतिशत वृद्धि (%)	p-मान
संप्रेषण कौशल	4.05	3.12	29.8	<0.001
तकनीकी कौशल	3.87	2.96	30.7	<0.001
समस्या-समाधान	3.92	3.18	23.3	<0.001
उद्यमिता दृष्टिकोण	3.65	2.84	28.5	<0.001
डिजिटल साक्षरता	3.78	2.92	29.5	<0.001

स्रोत: क्षेत्र-अध्ययन सर्वेक्षण आँकड़े; एसपीएसएस विश्लेषण (2021)

तालिका 5 दर्शाती है कि सहभागी विद्यार्थियों के सभी कौशल आयामों में 23 से 31 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। तकनीकी कौशल में सर्वाधिक 30.7 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, जो पीएमकेवीवाई के अल्पकालिक तकनीकी प्रशिक्षण मॉड्यूलों का प्रतिफल है। संप्रेषण एवं डिजिटल साक्षरता में लगभग 30 प्रतिशत वृद्धि से ज्ञात होता है कि सरकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम आधुनिक रोजगार-योग्यता आवश्यकताओं के अनुरूप कौशलों का संवर्धन कर रहे हैं।

तालिका 6: सरकारी योजनाओं में बाधाओं का प्रतिशत वितरण

बाधा	प्रतिशत (%)
जानकारी का अभाव	36.6
शैक्षिक कार्यभार	41.5
संस्थागत समर्थन की कमी	39.0
समय की कमी	55.1
प्रशिक्षण केंद्रों की दूरी	28.4

स्रोत: क्षेत्र-अध्ययन सर्वेक्षण आँकड़े (2021); तुलनीय आँकड़े देबनाथ (2021)

तालिका 6 के अनुसार समय की कमी (55.1%) सहभागिता की सबसे बड़ी बाधा है, जो शैक्षिक कार्यभार (41.5%) से जुड़ी हुई है। संस्थागत समर्थन की कमी 39 प्रतिशत तथा जानकारी का अभाव 36.6 प्रतिशत विद्यार्थियों ने स्वीकार किया। ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण केंद्रों की दूरी (28.4%) भी एक महत्त्वपूर्ण बाधा है। ये निष्कर्ष नीति-निर्माताओं को व्यावहारिक दिशा-निर्देश प्रदान करते हैं।

6. विवेचना

प्रस्तुत अध्ययन के परिणाम स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करते हैं कि झाँसी जिले के स्नातक विद्यार्थियों के व्यक्तित्व एवं कौशल विकास पर सरकारी योजनाओं का सकारात्मक एवं सांख्यिकीय रूप से सार्थक प्रभाव है। प्रथम उद्देश्य के संदर्भ में, तालिका 4 ने सिद्ध किया कि एनएसएस एवं अन्य योजनाओं में सहभागिता करने वाले विद्यार्थियों के आत्मविश्वास (4.12 बनाम 3.34), नेतृत्व क्षमता (4.08 बनाम 3.21), सामाजिक उत्तरदायित्व (4.21 बनाम 3.18) तथा टीम-कार्य भावना (4.15 बनाम 3.38) में अति-सार्थक अंतर है। ये निष्कर्ष भारती एवं आनंद (2021) के कानपुर अध्ययन से पूर्णतः मेल खाते हैं, जिन्होंने एनएसएस एवं गैर-एनएसएस छात्राओं में महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व अंतर पाया था। पाण्डेय (2015) के नासिक अध्ययन में भी सात-दिवसीय एनएसएस शिविर के पूर्व-पश्चात मूल्यों में सार्थक वृद्धि देखी गई थी, जो प्रस्तुत अध्ययन की पुष्टि करती है। मेहरोत्रा (2014) ने लखनऊ विश्वविद्यालय में बीस वर्षों

के अनुभव के आधार पर बारह व्यक्तित्व लक्षणों का विकास सिद्ध किया, जो हमारे परिणामों के सैद्धांतिक आधार को दृढ़ करता है। राव एवं वुप्पुलूरी (2015) तथा सेठी एवं अन्य (2019) के अध्ययनों में भी एनएसएस सहभागिता से सामाजिक चेतना, नेतृत्व एवं संप्रेषण कौशल में वृद्धि का प्रमाण मिला है।

द्वितीय उद्देश्य के संदर्भ में, तालिका 5 ने दर्शाया कि कौशल विकास के सभी आयामों – संप्रेषण (29.8%), तकनीकी (30.7%), समस्या-समाधान (23.3%), उद्यमिता (28.5%) तथा डिजिटल साक्षरता (29.5%) – में सहभागियों ने उल्लेखनीय श्रेष्ठता प्रदर्शित की। ये निष्कर्ष चौधरी एवं वर्मा (2020) के व्यवस्थित साहित्य समीक्षा के निष्कर्षों से मेल खाते हैं, जिन्होंने पीएमकेवीवाई एवं एनएसडीसी के माध्यम से कौशल विकास पर सकारात्मक प्रभाव दर्ज किया है। यथीश कुमार एवं रम्या (2017) ने भी पाया कि अधिकांश युवा स्किल इंडिया अभियान से जागरूक हैं तथा तकनीकी कौशल अर्जन में रुचि रखते हैं। तालिका 1 के राज्यवार आँकड़े दर्शाते हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षण की मात्रा (15.90 लाख) अधिक है, परंतु नियोजन दर (21.3%) तेलंगाना (35.1%) से कम है। राव (2018) के अध्ययन में भी यह निष्कर्ष मिला था कि उत्तर प्रदेश में नियोजन की दर मध्य प्रदेश एवं तमिलनाडु से कम है। यह असमानता राज्य-स्तरीय क्रियान्वयन में सुधार की आवश्यकता को रेखांकित करती है। तालिका 3 के अनुसार एनएसएस के प्रति 78.4 प्रतिशत जागरूकता के बावजूद सहभागिता मात्र 28.1 प्रतिशत होना चिंताजनक है। तालिका 6 के अनुसार समय की कमी (55.1%), शैक्षिक कार्यभार (41.5%) एवं संस्थागत समर्थन की कमी (39.0%) प्रमुख बाधाएँ हैं, जो देबनाथ (2021) के त्रिपुरा अध्ययन के समान निष्कर्षों को प्रतिध्वनित करती हैं।

बुंदेलखंड क्षेत्र की विशिष्ट सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियाँ कृषि-निर्भरता, सूखा-प्रवणता एवं अल्प-औद्योगिकीकरण के कारण यहाँ सरकारी योजनाएँ युवाओं हेतु जीवन-रेखा सिद्ध हो सकती हैं। तथापि, भारत की उच्च युवा बेरोजगारी दर 20.82 प्रतिशत (विश्व बैंक, 2021) एवं स्नातकों में अपेक्षाकृत अधिक बेरोजगारी (घोष एवं कुमार, 2021) चिंतनीय है। अहमद (2016) के अनुसार 2022 तक 40.29 करोड़ कुशल श्रमिकों का लक्ष्य था, परंतु क्षेत्रीय असमानताएँ इस लक्ष्य की प्राप्ति में बाधक हैं। प्रस्तुत अध्ययन यह स्पष्ट संकेत देता है कि झाँसी जैसे जिलों में योजनाओं की पहुँच, गुणवत्ता एवं उद्योग-शिक्षा समन्वय में सुधार से ही जनसांख्यिकीय लाभांश का सम्यक उपयोग संभव है (शर्मा एवं सक्सेना, 2020)।

7. निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध से यह स्पष्ट होता है कि झाँसी जिले के स्नातक विद्यार्थियों के व्यक्तित्व एवं कौशल विकास में सरकारी योजनाओं की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण एवं सकारात्मक है। एनएसएस, पीएमकेवीवाई, यूपीएसडीएम तथा डीडीयू-जीकेवाई जैसी योजनाओं ने आत्मविश्वास, नेतृत्व, संप्रेषण, तकनीकी कौशल एवं सामाजिक उत्तरदायित्व जैसे आयामों में मापनीय सुधार लाया है। सहभागी एवं गैर-सहभागी विद्यार्थियों के मध्य सांख्यिकीय रूप से सार्थक अंतर परिकल्पना की पुष्टि करता है। तथापि, अध्ययन ने जागरूकता एवं सहभागिता के मध्य अंतराल, समय की कमी, संस्थागत समर्थन का अभाव एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँच की समस्याओं को भी उजागर किया। सुझाव है कि महाविद्यालयों में जागरूकता अभियान, लचीली समय-सारणी, उद्योग-शिक्षा समन्वय, स्थानीय कौशल केंद्रों की स्थापना तथा प्रोत्साहन-तंत्र के माध्यम से सहभागिता बढ़ाई जाए। नीति-निर्माताओं को बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रीय संदर्भ में विशेष पैकेज तैयार करना चाहिए ताकि जनसांख्यिकीय लाभांश का यथार्थ उपयोग संभव हो।

संदर्भ-सूची

1. अहमद, टी. (2016). भारत में कौशल विकास – भारत सरकार की प्रमुख पहलें। *जर्नल ऑफ एजुकेशन एंड प्रैक्टिस*, 7(15), 99-101. https://www.iiste.org/Journals/index.php/JEP/article/view/30661
2. भारती, जे., एवं आनंद, ए. (2021). राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) विद्यार्थियों के व्यक्तित्व लक्षण। *इंडियन जर्नल ऑफ एप्लाइड रिसर्च*, 11(6), 45-47. https://www.researchgate.net/publication/352720909

3. चौधरी, आर., एवं वर्मा, एन. (2020). भारत में कौशल विकास शोध: एक व्यवस्थित साहित्य समीक्षा एवं भविष्य का शोध एजेंडा। *बेंचमार्किंग: एन इंटरनेशनल जर्नल*, 27(10), 2891-2912. https://doi.org/10.1108/BIJ-07-2019-0309
4. देबनाथ, एस. (2021). उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों के प्रति एनएसएस की भूमिका। *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ट्रेंड इन साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट*, 3(4), 1245-1248. https://doi.org/10.31142/ijtsrd23564
5. घोष, ए. के., एवं कुमार, ए. (2021). द्रुत आर्थिक विकास के काल में भारत का गहराता रोजगार संकट। *द इंडियन जर्नल ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स*, 64(2), 247-279. https://doi.org/10.1007/s41027-021-00321-1
6. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (2021). भारत में रोजगार, शिक्षा एवं प्रशिक्षण से बाहर युवा (एनईईटी): 2000-2019. आईएलओ, जिनेवा. https://www.ilo.org/publications/young-persons-not-employment-and-education-neet-india-2000-2019
7. कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (2021). वार्षिक रिपोर्ट 2020-21. भारत सरकार, नई दिल्ली. https://www.msde.gov.in/sites/default/files/2021-09/Annual%20Report%202020-21%20English.pdf
8. युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय (2019). राष्ट्रीय सेवा योजना मैनुअल. भारत सरकार, नई दिल्ली. https://yas.nic.in/sites/default/files/NSS-manual.pdf
9. मेहरोत्रा, एस. (2014). समुदाय आधारित गतिविधियों द्वारा शिक्षकों के व्यक्तित्व का निर्माण। *लाइफ साइंसेज लीफलेट्स*, 7(1), 18-25. https://ndpublisher.in/admin/issues/lcv7n1e.pdf
10. पाण्डेय, ए. आर. (2015). एनएसएस के विद्यार्थियों के व्यक्तित्व लक्षणों पर प्रभाव। *रिसर्च फ्रंट*, 3(1), 67-72. https://www.academia.edu/10402740/EFFECT_OF_NSS_ON_PERSONALITY_TRAITS_OF_STUDENTS
11. राव, के. के., एवं वुप्पुलूरी, ए. (2015). सेवा-शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों का व्यक्तित्व विकास: राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) पर अध्ययन। *जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी*, 6(2), 219-225. https://doi.org/10.1080/09766634.2015.11885664
12. राव, एस. (2018). कुशलों का रोजगार: पीएमकेवीवाई 2.0 का नियोजन विश्लेषण। *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्रिएटिव रिसर्च थॉट्स*, 6(1), 749-760. https://www.ijcrt.org/papers/IJCRT1872093.pdf
13. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (2025). प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का निष्पादन लेखा-परीक्षण, रिपोर्ट संख्या 20 / 2025. नई दिल्ली. https://cag.gov.in/uploads/download_audit_report/2025/Report-No.-20-of-2025_PA-PMKVY_English-PDF-A-06943abec463479.68516873.pdf
14. सक्सेना, एस. (2014). भारत में कौशल विकास कार्यक्रम: एक साहित्य समीक्षा। *रिसर्च जर्नल ऑफ सोशल साइंस एंड मैनेजमेंट*, 4(7), 156-162. https://www.researchgate.net/publication/332342669
15. सेठी, एन., जैन, एस., एवं भगत, एन. (2019). दंत-चिकित्सा शिक्षा में राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रभाव। *जर्नल ऑफ इंडियन एसोसिएशन ऑफ पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री*, 17(3), 220-225. https://doi.org/10.4103/jiaphd.jiaphd_57_19
16. शर्मा, एस., एवं सक्सेना, ए. (2020). भारत में जनसांख्यिकीय लाभांश एवं कौशल विकास। *एशियन जर्नल ऑफ रिसर्च इन सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज*, 10(8), 95-104. https://doi.org/10.5958/2249-7315.2020.00263.6
17. व्हीबॉक्स (2021). इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2021. व्हीबॉक्स, सीआईआई, एआईसीटीई एवं यूएनडीपी. https://wheebox.com/india-skills-report.htm

18. विश्व बैंक (2021). भारत में युवा बेरोजगारी दर: रुझान एवं विश्लेषण. विश्व बैंक डेटाबेस. https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.1524.ZS?locations=IN
19. यथीश कुमार, डी., एवं रम्या, के. आर. (2017). स्किल इंडिया द्वारा आर्थिक समृद्धि: प्रमुख सफलता कारक एवं चुनौतियों का अध्ययन। *आईओएसआर जर्नल ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट*, 19(5), 50-54. https://doi.org/10.9790/487X-1905045054
20. यादव, आर. एवं अग्रवाल, पी. (2020). उच्च शिक्षा संस्थानों में सेवा-शिक्षण के माध्यम से व्यक्तित्व विकास। *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंडियन साइकोलॉजी*, 8(2), 1023-1031. https://doi.org/10.25215/0802.118

Cite this Article:
रहीस अली[1], डॉ. धर्मेंद्र सिंह[2], "झाँसी जिले में सरकारी योजनाओं द्वारा स्नातक विद्यार्थियों के व्यक्तित्व एवं कौशल विकास का अध्ययन" *Shiksha Samvad International Open Access Peer-Reviewed & Refereed Journal of Multidisciplinary Research, ISSN: 2584-0983 (Online), Volume 03, Issue 03, pp.290-297, March-2026. Journal URL: https://shikshasamvad.com/*

This is an Open Access Journal / article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC BY-NC-ND 3.0) which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. All rights reserved.

CERTIFICATE

of Publication

This Certificate is proudly presented to

रहीस अली[1], डॉ. धर्मेंद्र सिंह[2]

For publication of research paper title

झाँसी जिले में सरकारी योजनाओं द्वारा स्नातक विद्यार्थियों के व्यक्तित्व एवं कौशल विकास का अध्ययन

Published in 'Shiksha Samvad' Peer-Reviewed and Refereed Research Journal and E-ISSN: 2584-0983(Online), Volume-03, Issue-03, Month March 2026.

Dr. Neeraj Yadav
Editor-In-Chief

Dr. Lohans Kumar Kalyani
Executive-chief- Editor

Note: This E-Certificate is valid with published paper and the paper must be available online at: https://shikshasamvad.com/